U.S. INVESTMENT IN SAIL

3437. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether Government has embarked on a bid to attract US investment in the steel sector;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that an Indian delegation of Steel Ministry is visiting USA to offer equity in SAIL to various multi-national companies;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether any proposals for joint sector ventures in Steel are being proposed with US firm; and

(f) whether any ground work has been done before the delegation setting out for USA ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) and (b) In view of resource constraints, Govrenment do not propose to set up New Steel Plant in the Public Sector. Future investment in the Steel Industry will therefore have to come from private sources both indigenous and foreign. The Iron and Steel Industry has already been placed in the list of high priority industries where there is a provision for automatic approval of foreign equity investment upto 51 per cent provided that the foreign investment covers the cost of imported capital goods.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) SAIL proposes to float a Joint Venture Company with M/s. USX Engineers and Consultant (UEC), a company incorporated in USA. A Memorandum of Understanding has been reached between SAIL and UEC for floating of a Joint Venture Company for carrying out Information Technology Services in India and abroad. The proposed Company will have an authorised share capital of Rs. 100 lakhs with proposed equity participation between SAIL and UEC in the ratio of 40 : 60.

(f) Does not arise in view of answer to part (c).

कुमारधुबी फायरक्ले एण्ड सिलिका वर्क्स लिमिटेड धनबाद, बिहार

3438. श्री कामेश्वर पासवान : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के असहयोग के कारण बड़े एण्ड कम्पनी के अधीन कुमारधुबी फायरक्ले एण्ड सिलिका वर्क्स लिमिटेड की मुख्य शेयर धारक मैसर्स टाटा एण्ड ए. पी. ग्रीन कम्पनी को इसके कार्यकरण में रुचि समाप्त हो गयी है और अकुशल तथा भ्रष्ट प्रबंधन के कारण यह कम्पनी रुग्ण हो गयी है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात मंत्रालय की त्रुटि के कारण औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा प्रथम दृष्टया इस कम्पनी को बन्द करने की सिफारिश किए जाने की संभावना है, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर "हां" में हों, तो इस उद्योग को पुनर्जीवित करने और इस उद्योग में कार्यरत 1623 कर्मकारों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) कुमारधुबी फायरक्ले एण्ड सिलिका वर्क्स लिमिटेड (के. एफ. एस. डब्ल्यू.) तत्कालीन बड़े ग्रुप की कम्पनियों में से एक है। इसे सरकार ने 1980 में अधिग्रहित किया था। हालांकि, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) 1988 में निदेशक मंडल से अलग हो गया। फिर भी टिस्को और ए. पी. ग्रीन, दोनों ही इस कम्पनी के शेयर

धारक हैं । इनके पास क्रमशः 30% और 20% शेयर हैं ।

संयंत्र और मशीनरी के ठीक प्रकार से अनुसरण न करने और आधुनिकीकरण के अभाव और इस्पात संयंत्रों द्वारा अपेक्षित उच्च मूल्य उत्पादों के उत्पादन में सक्षम न होने के कारण के. एफ. एस. डब्ल्यू. रुग्ण हो गई। इस कारण के. एफ. एस डब्ल्यू. न्यून मूल्य के भारी मात्रा और आंशिक रूप से माध्यम मूल्य के कुछ उत्पादों के अधिक टनभार का उत्पादन कर सका । विगत वर्षों में कम्पनी उत्पादन में कमी हुई है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है । लगातार खराब कार्य-निष्पादन के कारण के. एफ. एस. डब्ल्यू. रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की शर्तों के अनुसार रुग्ण कम्पनी बन गई। इस समय यह मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के पास है । बी. आई. एफ. आर. द्वारा कई बार सुनवाई हो चुकी है परन्तु बी. आई. एफ. आर. द्वारा अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

PURCHASE OF UNIFORM IN ROURKELA STEEL PLANT

3439. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rourkela Steel Plant has floated tender for purchase of uniforms, and shoes for its employees in the past two months;

(b) whether the details of offers have been received by the RSP from both private and public sector;

(c) whether any Central Government Undertaking has also participated in the tender;

(d) if so, the details thereof; and

(e) what protection is being given to the Central Government Undertakings ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) No, Sir. Tenders were however floated in the 1st quarter of 1993.

(b) and (c) Yes, Sir.

(d) M/s. Bharat Leather Corporation, a Central Govrenment Undertaking has participated in the tender for boots and shoes and their offer s under scrutiny by the plant.

(e) No special protection is provided to Central Government Undertaking in the purchase of boots and shoes.

इंजीनियरी सामान सहायता कोष (इंजीनियरी गुडस असिस्टेन्स फंड) की स्थापना

3440. डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

श्री राम जेठमलानी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में इंजीनियरी सामान के, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरी सामान सहायता निधि की स्थापना की गयी है

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है, कि इस कोष के माध्यम से इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रति पूर्ति योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है,

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त योजना के अन्तर्गत लगभग 450 करोड़ रुपए के दावे भुगतान हेतु लम्बित हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात पर लगाए जाने वाले उपकर की दरों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि (ई. जी. ई. ए. एफ.)